

विचार बिन्दु

विजय गर्व और प्रतिष्ठा के साथ आती है पर यदि उसकी रक्षा पौरुष के साथ न की जाय तो अपमान का ज़हर पिला कर चली जाती है। –मुक्ता

देश व लोकतंत्र के हित में चुनाव आयोग केवल सक्रिय ही नहीं, किंतु निष्पक्ष भी हो और ऐसा दिखे भी

ल गभग निम्न आशय की बात चुनाव आयोग के हवाले से प्रिंट, टीवी व सोशल मीडिया में घूम रही है :--
--
पर उठाए जा रहे बेबुनियादी सवालो से डरकर, चुनाव आयोग ऐसे लोगों के बहकावे में आकर --
1. मरे हुए मतदाताओं
2. स्थाई तौर से प्रवास के गए मतदाताओं
3. दो जगह वोट बनवा चुके मतदाताओं
4. फर्जी मतदाताओं
5. विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी बात डालने वाले लोगों को पहले बिहार में और फिर पूरे देश में, संविधान के विरुद्ध जाकर बात डालने की अनुमति दें???

चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित एक शक्तियुक्त आयोग है जिस पर देश में निष्पक्ष चुनाव करने का बहुत बड़ा दायित्व है। राजनीतिक दलों को भी बिना बात उसकी गरिमा को बेवजह ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, यह बात तो सामान्य से सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी मानेगा।

किंतु उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि चुनाव आयोग भी पूर्ण निष्पक्षता से अपना दायित्व निभाए।

कौन इस से असहमत होगा कि मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों से हटे। यह रूटीन एक्सरसाइज चुनाव आयोग नियमित रूप से करता आया है, किसी ने प्रश्न उठाया क्या कि ऐसा नहीं किया जाए?? तो फिर यह प्रश्न ही क्यों??

इसी प्रकार जिन मतदाताओं का नाम दो जगह मतदाता सूचियों में है उनका नाम एक जगह से विलोपित होना चाहिए किन्तु ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह किस स्थान पर मतदान करना चाहता है?? क्या नहीं हो ऐसा?? जिन लोगों को रोजी-रोटी व सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए ग्रामीण व शहरी दोनों जगह रहना पड़ता है जैसे कि अल्पायुभोगी दिहाड़ी काम वाले लोग, किसान – मजदूर आदि। सामान्य बुद्धि तो कहती है मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करते वक़्त ऐसे चिन्हित लोगों को अवसर दें कि वे कहां के मतदाता रहना चाहते है? केवल बीएलओ के द्वारा भरे या भराये गए गणना पत्र के आधार पर नाम काग़त सरासर अन्याय होगा और चुनाव आयोग की साख़ भी कुछ तो कम होगी ही, चुनाव आयोग माने या न माने।

इसी प्रकार जिन मतदाताओं में स्थाई तौर पर पुराना निवास छोड़ कर नई जगह रहना शुरू कर दिया उनका नाम भी हटना चाहिए और मैं समझता हूं किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोधी नहीं किया है। किंतु ऐसे मामलों में पूर्णत: निष्पक्ष रूप से जांच तो होनी चाहिए कि यह तथ्य सही है या BLO की लापरवाही है या कहीं BLO या BLA की मिलीभगत तो नहीं है, किसी दूसरे पक्ष के वोटर्स का नाम कटवाने की???

हर चुनाव के बाद पोलिंग बुथ के बाहर ऐसे व्यक्ति शिकायत करते मिलते है कि पहले उसका नाम था अब नहीं, क्यों??

और अब आयोग के द्वारा, मतदाता सूचियों में से फर्जी व विदेशी मतदाताओं के हटाने की बात पर विचार करे। शायद ही कोई असहमत होगा कि फर्जी व विदेशी लोगों के नाम मतदाता सूचियों में से हटने चाहिए? प्रश्न यह है कि आयोग ने यह प्रश्न पूछा क्यों? सबसे पहले आयोग ही स्पष्ट करे कि फर्जी और विदेशी मतदाताओं की पहचान कैसे की? ऐसे लोगों की सूची जारी करे जिन्हें आयोग फर्जी या विदेशी मानता है और उसके आधार बताए।

ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में, निम्न कारणों से होना संभव है :--
की निष्क्रियता, लापरवाही के कारण या फिर BLO और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मिलीभगत हो। यह मिली भगत पहले संभव थी तो अब भी हो सकती है। बहुत से लोगों को झुटमूट मृत बताया जा सकता है, निवास छोड़कर अन्यत्र बसना बताया जा सकता है।

इसलिए आयोग को आगामी एक माह में ऐसे समस्त लोगों जिन्हें मृत या निवास छोड़ गए बात रहे है, उनकी बुधवार सूची बुथ पर, पंचायतों में, पटवारियों के पास, तहसील कार्यालयों में व पॉलिटिकल पार्टियों को उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जिन को आपत्ति हो वे आपत्तियां दर्ज कर सकें।

जो समाचार है उनके अनुसार, आयोग को ज्ञात हुआ है कि विदेशी व फर्जी मतदाताओं के वोट दूसरे लोग डालते है। यह तो अत्यंत ही गंभीर बात आयोग में बताई है। फिर तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही संदेह के घेर में आ जाएगी?

अगर आयोग के हवाले से छपी खबर सही है तो फिर आयोग को पता है कि किन फर्जी व विदेशियों के वोट कौन डालता-डलवाता है???? फिर तो आयोग विस्तृत सूचनाएं देश के सामने आने दे।

चलते-चलते, आम आदमी की जिज्ञासा है कि कौन देश का नागरिक कोन विदेशी, इसकी पहचान कौन दफ़्तर कौन अधिकारी करते हैं? नागरिक होने का प्रमाण पत्र लेना हो तो चुनाव कार्यालय में दरखास्त दें या अब जो वोटरलिस्ट जारी करेगा आयोग वही प्रमाण पर्याप्त होगा नागरिकता दिखाने के लिए। वैसे कानून जानने वाले लोग मानते है कि चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच का अधिकार नहीं। अब यह सही है या नहीं यह तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार या चुनाव आयोग जाने।

यों ही, एक बात सुनते आए है कि न्याय हो यही पर्याप्त नहीं, न्याय होता दिखना भी चाहिए। एक न्यायाधिकारी के सामने मुकदमा पेश होने के बाद सभी पक्षकारों और उनके पैरवी कर्ताओं को सुना जाता है। फैसले में सारी बातें विस्तार से लिखी जाती है। जो भी कानून के बातें कही जाती है वे लिखी जाती है। इन सभी पर न्यायाधीकारी अपना मत व्यक्त कर फैसला देता है। इस से न्याय हुआ दिखता है। फैसला तो यों भी हो सकता है कि सब को सुनने के बाद यह मानता हूं कि यह यह बात सही है और यह आदेश दिया जाता है ----? नहीं? किंतु नहीं क्यों कि ऐसा करने से न्याय होता दिखता नहीं।

अल्पज्ञानि सामान्य आदमी का तो मानना है कि यह बात चुनाव आयोग भी लागू होती है। चुनाव आयोग कोई छोटे अधिकारियों का दफ़्तर नहीं जहां कोई गलती कर दे तो ऊपर के दफ़्तरों में जाने के रास्ते है। यदि चुनाव आयोग मतदाताओं का नाम बिना पूर्ण- विस्तृत जांच के नाम काटी दे तो लोकतंत्र में इस से घातक ओर क्या बात होगी??

चुनाव आयोग का सम्मान होना ही चाहिए किंतु इसके लिए आयोग को भी निष्पक्ष दिखना ही होगा।

–अतिथि सम्पादक,
महावीर सिंह, पूर्व आइ ए एस

राशिफल
शनिवार 26 जुलाई, 2025
 सावन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शनिवार, विक्रम संवत २०८२, आश्लेषा नक्षत्र दिन ३:५२ तक, व्यतिपात योग रात्रि ४:०६ तक, बालव करण दिन ११:०२ तक, चन्द्रमा आज दिन ३:५२ से सिंह राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-कर्क, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रृंगोन्तति, सिंजारा, अश्वत्थ मारूती पूजन, व्यतिपात पुण्य है। आज शुक्र मिथुन राशि में प्रात: ८:५६ पर प्रवेश करेगा। श्रेष्ठ चौचड़िया: शुभ ७:३२ से ९:१२ तक, चर १२:३३ से २:१४ तक, लाभ-अमृत २:१३ से ५:३४ तक। राहुकाल: ९:०० से १०:३० तक। सूर्योदय ५:५२, सूर्यास्त ७:१४



अर्पिता माथुर

क्या हम सच में चौंद पर पहुँच गए है या अब भी पुरानी सोच में जकड़े है?। “सोचिए, जिस लड़की ने तीन साल पहले अपने सपनों की शादी की थी, वही दहेज के बोझ से दबकर अपनी जान दे बैठी।”

राजस्थान के जयपुर में हाल ही में दो विवाहित महिलाओं की मौत की खबर आई। वैशाली नगर में तीन साल पहले लव मैरिज करने वाली महिला ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर श्याम नगर में एक और विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई जहाँ पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। ये घटनाएँ चौकता है और सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में चौंद पर पहुँच गए है या अब भी पुरानी सोच में जकड़े

कारगिल युद्ध : भारतीय सेना और सैनिकों की गौरव गाथा



डॉ. जे.के. गर्ग

निरंदेह कारगिल संघर्ष दुनियांभर के पहाड़ी इलाकों में अत्याधिक ऊंचाई पर लड़ी गई लड़ाईयों में से एक लड़ाई है। कारगिल संघर्ष परमाणु वम शक्ति सम्पन्न भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ पहला सशस्त्र युद्ध था। जहाँ १९६५ में हम लाहोर तक पहुंच गये और पाकिस्तान के हॉसले पस्त कर दिए थे इस युद्ध की परिणीती तास्क्द समझोते में हुई थी, वहीं १९७१ में पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित करके एक नये राष्ट्र बंगलादेश को जन्म दिया था। यह युद्द इंदिराजी जी के विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण था, वहीं बीसवीं शदी की निर्णायक एकमात्र युद्ध भी था जिसमें ९३००० से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर भारतीय सेना के गौरव को उज्ज्वलम शिखर पर पहुंचा कर विजय पताका फहरा कर तिरों की शान बढ़ाई थी।

कारगिल युद्ध को मोटे तौर पर

है?। और भी कई ऐसी घटनाओं ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम चाहे चौंद तक पहुँच जाए लेकिन समाज की कुछ रीति-रिवाजों का बोझ जीवन भर सहना पड़ेगा। वैसे रीति-रिवाजों के विरोध में नहीं हूँ मैं लेकिन कुछ रीति-रिवाजों का अपना ऐतिहासिक महत्त्व रहा है, बस समाज ने बिना ज्ञान के अपनी मानसिकता के बल पर अन्य प्रकार से उन्हें ग्रहण किया है और अब आने वाली पीढ़ी पर थोप रहे है।

न केवल भारत में बल्कि यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में भी दहेज प्रथा का लम्बा इतिहास है। भारत में इसके और भी कई नाम है जैसे हूँडा या वर-दक्षिणा। इतिहास में इसे एक परम्परा के रूप में देखा जाता था जिसका ऐतिहासिक सन्दर्भ कई लेखों और चित्रों में भी मिलता है। जिसे यहाँ प्रदर्शित करना एक नयी बहस शुरू कर देगा। क्योंकि मेरा और मेरे जैसे कितने पत्रकारों का यही मकसद रहने वाला है कि इस प्रथा को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाये न कि जंग से प्रस्तुत किया जाए... खैर.. भारत में दहेज, भले ही वर्ष १९६१ से दहेज निषेध अधिनियम के तहत अवैध घोषित है, फिर भी इसे आज भी एक सामाजिक प्रथा के रूप में देखा जाता है। वधू यानि लड़की के परिवार द्वारा नक्रद या वस्तुओं के रूप में यह वर यानि लड़के के परिवार को दिया जाता है। कई परिवार इसे विवाह का ज़ररी हिस्सा मानते है और अक्सर इसे उपहार का नाम

आँकड़ों की बात की जाए तो साल २०१७ से २०२२ के बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर साल औसतन ७,००० दहेज से संबंधित हत्याएँ दर्ज हुई। वैसे में ये कहूँगी की के आँकड़ें अपवादित भी हो सकते है क्योंकि दहेज से होने वाली अनेक मौतें रिपोर्ट ही नहीं की जातीं, जो इस समस्या की गंभीरता और हम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक है उसकी तरफ एक इशारा है। वहीं दहेज के लिए तंग करने पर कानून सख्त सज़ा देता है जैसे धारा ४९८ -ए: अगर पति या उसके घरवाले दहेज की मांग करके पत्नी को परेशान करें, तो उन्हें ३ साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है।

धारा ४०६: अगर पत्नी का गहना या उसका सामान वापस नहीं करते, तो ३ साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो

सकते है। धारा ३०४-बी: अगर शादी के ७ साल के अंदर दहेज की वजह से महिला की संदिग्ध मौत हो जाए, तो ७ साल से लेकर उन्कैद तक की सज़ा हो सकती है। हालांकी दहेज का विवाह के साथ अटूट संबंध है लेकिन दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ का अनुच्छेद ३ निर्दिष्ट करता है कि दहेज देने या लेने का दंड उन उपहारों पर लागू नहीं होता है जो दुल्हा या दुल्हन को शादी के समय दिए जाते है जब उनकी कोई मांग नहीं की जाती है।

गॉव हो या शहर, अमीर हो या गरीब – दहेज प्रथा को जड़ें बहुत गहरी है जिसका दूसरा छोर दूँधने से भी नहीं मिलेगा। जहाँ एक और महिलाओं को अब भी यानि मॉडर्न समाज में दहेज के लिये उल्टीड़न, मारपीट और आत्महत्या जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जाँच प्रक्रियाएँ इतनी लंबी होती है की दोषियों को सजा मिलना और बेक़रूर को न्याय मिलना ऊँट के मुँह में जीरा मिलने समान है। सबसे बड़ी समस्या तो सोच की ही है. बेटी को आज भी ‘परया धन’ समझा जाता है। वहीं दिखावा और समाज में ‘स्टेटस मेन्टेन’ करने की होड़ मची है । अपराधियों में कानून का डर ही नहीं है क्योंकि कई केस दबा दिए जाते है या रिपोर्ट नहीं होते। अपराधियों के हॉसले और बुलंद हो जाते है। कुल मिलाकर समस्या समाज की मानसिकता में है। दोनों पक्षों को अपना अपना सामाजिक स्टेटस बढ़ाना है चाहे आंतरिक स्थिति

–अर्पिता माथुर (पत्रकार)

कारगिल युद्ध : भारतीय सेना और सैनिकों की गौरव गाथा

सेना प्रत्यक्ष रूप मेंइंडस युद्ध में शामिल थी। कारगिल- ठाऊ सेक्टर में हुए संघर्ष में लगभग ३००० भारतीय सैनिकों ने भाग लिया वहीं पाकिस्तान के नियमित सैनिकों के अलावा करीब ५००० घुसपैटीयें ने भी पाक सैनकों की मदद की थी। भारतीय सेना ने इस लड़ाई में बोफोर्स तोपों का प्रयोग किया इन तोपों ने दुश्मनों पर कहर बरपा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत कठिन भौगोलिक परिस्थतियों के बावजूद थल सैनिकों की सहायता की थी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के अंतर्गत पाकिस्तानी बंदरगाहों विशेषतया कराची बंदरगाह की नाके बंदी को हल करने का प्रयत्न करने में नियन्त्रण रेखा के उल्लंघन को रोक कर संघर्ष के पूर्व वाली स्थिती पर लोटने को कहा। अमेरिकन राष्ट्रपति क्लिंटन और नवाज शरीफ के संयुक्त व्यक्तय में नियन्त्रण रेखा का सम्मान करते हुए भारत-पाकिस्तान के विवादों को बातचीत से शांतीपूर्ण तरीकों से सुलझाने को कहा। चारों ओर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ ने बचे हुए पाकिस्तान के सैनिकों को भारतीय सीमा के अन्दर वाले क्षेत्र से पीछे हट जाने का आदेश दिया।

भारत की विजय के साथ २६ जुलाई १९९९ को संघर्ष समाप्त हुआ। कारगिल युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष २६ जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समस्त भारत में इस कारगिल युद्ध के दौरान अद्वुत राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना देखने को मिली थी। वहीं पाकिस्तान की पराजय के कारण पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई जिसकी परिणति में नवाज़ शरीफ़ निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर वहां की सेना के प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ़ राष्ट्रपति बन गए।कारगिल युद्ध के अनेकों शूरवीर बहादुर एवं फोलादी इरादों वाले जवानों में अतुल्य योगदान, विक्रम बत्रा एवं योगेन्द्र यादव तो प्रमुख हैं ही, भारत को उनके और उनके साथियों की वीरता तथा फोलादी देश भक्ति के इरादों से युद्ध में निर्णायक विजयश्री मिली थी। इस लड़ाई में मुब्छा विजय टाईगर हिल्स पर कब्ज़े पर थी।

कारगिल युद्ध के उपरोक्त नायकों के अतिरिक्त कारगिल संघर्ष के अन्य हीरों यथा कैप्टिन जेरी प्रेमराज, कैप्टिन शशि भूषण घडियाल, सुबेदार मुशनाथ सिंह एवं हवलदार सीसरमन गिल के योगदान को भी समूचा राष्ट्र हमेशा याद रक्खेगा। कारगिल विजय पर्व के २५वीं वर्ष गाँठ के मोके पर समूचा भारत कारगिल संघर्ष के समस्त शहीदों को शत: शत: नमन करता है और उनके देशभक्ति के जज्बे को सलाम भी। समूचा राष्ट्र कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारत की अखंडता परतिरछी नजर रखने वालों को कड़ी चेतावनी देता है कि वे अपनी नापाक हकतों से बात आयाँ जय हिंद जय किसान जय जवान। भारत का बच्चा करें उनका सम्मान और सलाम।

–डॉ. जे.के. गर्ग,
पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक कॉलेज शिक्षा जयपुर

औडेलगढी, निभेरा और चैकोरा, नदबई की लखनपुर, कटारा और परसवारा एवं बयाना की बंधबैरठा, सालाबाद और गाजीपुर ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खोले गए हैं। राज्य में इसके अतिरिक्त एक लाख लाभार्थियों को नि:शुल्क इंडव्रशन कुकटॉप वितरित करने का निर्णय लिया गया है। वेस्ट २ वैल्थ पार्क्स और क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डवलपमेंट सेंटर जैसे नवाचारों से पर्यावरण संरक्षण को तकनीकी मजबूती दी जा रही है। इसे गाँवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे ग्रामीणों को भी सामूहिक आयेजनों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की प्रेरणा मिलेगी।

यह लेख हरिओम सिंह गुर्जर, संयुक्त निदेशक, भरतपुर सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय और संतोष कुमारवत, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), पंचायतीराज विभाग ने लिखा है।



विधवा, एससी, एसटी जैसे वर्गों के लिए आधा किराया माफ़ कर सकती है। राज्य में अजमेर जिले में २७, अलवर में ३०, बालोतरा २७, बांसवाड़ा ३०, बांरा में २४, बाड़मेर में ३०, ब्यावर में १८, भरतपुर में २१, भीलवाड़ा में ३०, बीकानेर में २७,

बूंदी में १५, चित्तौडगढ़ में ३०, चूरू में २१, दौसा में ३०, डींग में १५, धौलपुर २०, डीडवाना-कुचामन में २१, दूंगरपुर में ३०, श्रीगंगानगर में २७, हनुमानगढ में २१, जयपुर में ३०, जैसलमेर में २१, जालौर में ३०, झुंझुनू में ३०, झालावाड़ में २४, जोधपुर ३०,

बुंदी में १५, चित्तौडगढ़ में ३०, चूरू में २१, दौसा में ३०, डींग में १५, धौलपुर २०, डीडवाना-कुचामन में २१, दूंगरपुर में ३०, श्रीगंगानगर में २७, हनुमानगढ में २१, जयपुर में ३०, जैसलमेर में २१, जालौर में ३०, झुंझुनू में ३०, झालावाड़ में २४, जोधपुर ३०,

बुंदी में १५, चित्तौडगढ़ में ३०, चूरू में २१, दौसा में ३०, डींग में १५, धौलपुर २०, डीडवाना-कुचामन में २१, दूंगरपुर में ३०, श्रीगंगानगर में २७, हनुमानगढ में २१, जयपुर में ३०, जैसलमेर में २१, जालौर में ३०, झुंझुनू में ३०, झालावाड़ में २४, जोधपुर ३०,

करोली २४, खैरथल-तिजारा १५, कोटा २०, कोटपुतली- बहरोड़ २०, नागीर २४, पाली २४, फलोदी २४, प्रतापगढ़ २४, राजसमंद २४, सलुम्बर में २०, सर्वाइयाधोपुर में २१, सीकर में ३०, सिराही में २०, टोंक २१ और उदयपुर में ३० ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना की जा चुकी है।

इस योजना के सफल संचालन से भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता के प्रति नई चेतना आई है। गरीब परिवारों को भी टैट किराये से राहत मिली है। शादी समारोह में टैट किराये में लगने वाला हजारों रूपये का खर्च बचने से बड़ी राहत मिली है, कचरे के ढेर, दुर्गंध, पर्यावरण क्षण का कुछ हद तक समाधान हुआ है। जिले की पंचायत समिति सेवर में ग्राम पंचायत हथैनी, जधीना और जाटौली रथवान, पंचायत समिति भुसावर की बल्लभगढ, निठार और पथैना, उच्चैन की भैंसा, पिचुना और सहना, वैर की समराया, सरसैना और पाली, रूपवास की

बुंदी में १५, चित्तौडगढ़ में ३०, चूरू में २१, दौसा में ३०, डींग में १५, धौलपुर २०, डीडवाना-कुचामन में २१, दूंगरपुर में ३०, श्रीगंगानगर में २७, हनुमानगढ में २१, जयपुर में ३०, जैसलमेर में २१, जालौर में ३०, झुंझुनू में ३०, झालावाड़ में २४, जोधपुर ३०,

बुंदी में १५, चित्तौडगढ़ में ३०, चूरू में २१, दौसा में ३०, डींग में १५, धौलपुर २०, डीडवाना-कुचामन में २१, दूंगरपुर में ३०, श्रीगंगानगर में २७, हनुमानगढ में २१, जयपुर में ३०, जैसलमेर में २१, जालौर में ३०, झुंझुनू में ३०, झालावाड़ में २४, जोधपुर ३०,